भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 670

06 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

भारत आटा वितरण हेतु मोबाइल वैन

670. डॉ. रामशंकर कठेरिया:

श्री राम कृपाल यादव:

श्री जनार्दन मिश्र:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए 'भारत आटा की बिक्री हेतु मोबाइल वैन चला रही है और यदि हां, तो उक्त कार्ययोजना के अंतर्गत कितने खाद्य पदार्थों को शामिल किए जाने का विचार है;

(ख) उक्त कार्ययोजना के अंतर्गत अब तक कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया गया है; और

(ग) भारत आटा की बिक्री हेतु उक्त योजना के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मोबाइल वैनें चलाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): भारत सरकार गेहूं और आटा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 'भारत आटा' ब्रांड के तहत अधिकतम रुपए 27.50/- किग्रा के एमआरपी पर स्थायी/गतिमान खुदरा दुकानों के माध्यम से केंद्रीय/राज्य सहकारी एजेंसियों द्वारा आटा के प्रसंस्करण और बिक्री के लिए गेहूं उपलब्ध करा रही है। भारत आटा के अतिरिक्त, केंद्रीय/राज्य सहकारी एजेंसियों द्वारा स्थायी/गतिमान खुदरा दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाली भारत दाल (चना दाल) और प्याज भी बेचा जा रहा है।

वर्तमान में, भारत आटा की बिक्री के लिए बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुल 261 मोबाइल वैन चल रही हैं।

*****